



गाजा के एक खेत में टाइल मोज़ैक का एक फर्श मिला है, जिस पर खूबसूरत पक्षी व अन्य जानवर चित्रित हैं। यह इतनी अच्छी स्थिति में है कि मानो हाल ही में मिट्टी में दबाया गया हो। जैतून की खेती करने वाले किसान, सलमान अल नबाहिन जब बुरेजी रिफ्यूजी कैम्प में जैतून के नए पौधे लगा रहे थे तब उन्हें और उनके पुत्र को यह प्राचीन अवशेष मिला। समझा जाता है कि, यह बायजेंटाइन काल का है। असल में कुछ नए पौधे जड़ नहीं पकड़ रहे थे इसलिए जब सलमान और उनके पुत्र ने जमीन खोदनी शुरू की, तब उनके आँजार किसी कठोर सतह से टकराए। खोज करने पर उन्हें मोज़ैक का यह फर्श मिला। कोई पुरातत्व विशेषज्ञ आकर देख पाता इससे पहले ही नबाहिन व उनके पुत्र ने इंटरनेट पर खोज शुरू की और मोज़ैक के स्ट्राइक के आधार पर पता लगाया कि यह संभवतया बायजेंटाइन काल का है। बायजेंटाइन साम्राज्य रोमन साम्राज्य का पूर्वी भाग था। बायजेंटाइन उन कई संस्कृतियों में से एक है, जिसने सदियों तक फिलिस्तीन क्षेत्र पर नियंत्रण रखा। इसके अलावा प्राचीन रोम, मिस्र, ऑटोमन क्रूसेडर स्टेट और बाइबिल कालीन फिलिस्तीन का भी इस क्षेत्र पर प्रभाव था।

‘ठगों की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) पर मंगलवार को आरोप लगाया कि यह पार्टी धोखेबाजों और रिक्कवरी करने वाली की है।

पार्टी मुख्यालय पर आयोजित एक प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि एक मनी लॉडिंग केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद धोखेबाज ने “आप” को प्रोटेक्शन मनी के रूप में 10 करोड़ रूपए देने और उसे राज्य सभा सदस्य बनाने के लिए अन्य 50 करोड़ रूपए देने का खुलासा किया है।

उसने दिल्ली के लैफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा कि चंद्रशेखर और दिल्ली के मंत्री सत्येन्द्र जैन तिहाड़ जेल में हैं और आपस में अच्छे मित्र हैं। वे यह दवाब बना रहे हैं कि उसने आप को जो पैसा दिया है, उसे सार्वजनिक ना किया जाए।

डा. पात्रा ने कहा कि दिल्ली में आप को ब्राह्म सिण्डिकेट सरकार चला रही है। इसमें एक तो जेल के भीतर है और दूसरी जेल के बाहर। उन्होंने कहा कि धोखेबाज सुकेश ने लैफ्टिनेंट गवर्नर को लिखे पत्र में खुलासा किया है कि दिल्ली के मंत्री सत्येन्द्र जैन वर्ष 2015 से उसके मित्र हैं और जैन ने उसे आप का राज्यसभा सदस्य बनाने का वादा किया था। उसने स्वयं को दक्षिण भारत के एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करवाने को लेकर “आप” को 50 करोड़ का डोनेशन भी दिया था।

यह दावा करते हुए कि तत्कालीन जेल मंत्री जैन ने उससे मुलाकात करने के लिए तिहाड़ का कई बार दौरा किया और जेल परिसर के भीतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2019 में उससे प्रोटेक्शन मनी भी ली। सुकेश ने दावा किया कि उसने 2 करोड़ की मंथली इन्टरलॉन्ट के रूप में “आप” को 10 करोड़ रूपए दिए थे। उसने जैन पर यह आरोप भी लगाया कि उनके कहने पर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जेल ने उसे घमकियां दीं।

दिल्ली में लैफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा योगा ट्रेनिंग रोकने को लेकर भी उसने अरविंद केजरीवाल का उपहास करते हुए कहा कि वास्तविकता में केजरीवाल एक ही योग आसन जानते हैं और वह है “भ्रष्टाचार आसन”।

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जरूरतें पूर्ण किए जाने के बाद डेढ़ वर्ष पूर्व लिस्टिंग के लिए तैयार था। जब यह तथ्य सामने आया कि मंगलवार को लिस्ट हुआ प्रकरण डेढ़ साल से ब्लॉक करके रखा हुआ था तो चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित ने अपनी खुद की रजिस्ट्री के लिए ही नोटिस जारी किया।

बैंच की अन्य जज बेला एम. त्रिवेदी थी। नोटिस में रजिस्ट्री को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपना स्पष्टीकरण देने के साथ ही इस प्रकरण को लिस्ट करने में हुए दीर्घकालीन विलम्ब के कारण भी बताए।

कोर्ट ने रजिस्ट्री को यह भी निर्देश दिया कि वह उन मामलों की भी लिस्ट प्रस्तुत करे जो लिस्टिंग के लिए तैयार हैं लेकिन कोर्ट की सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं है। कोर्ट ने रजिस्ट्री से कहा कि वह यह बताए कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई और इसके सुधार के क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं।

यह प्रकरण जिसने सुप्रीम कोर्ट को आक्रोशित किया, उसका संबंध उस मामले से है जो फिलहाल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में चल रहा है।

अजमेर दरगाह में अवैध व्यावसायिक निमाणों पर हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिये

आदेश के अनुसार नगर निगम को कहा गया है कि, दरगाह शरीफ में बनी इन “अनाधिकृत दुकानों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें”

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 1 नवंबर। अजमेर दरगाह शरीफ परिसर के अंदर 16 खंभा क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई जा रही दुकानों पर रोक लगाने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल और अनूप कुमार ढंड को खंडपीठ के समक्ष सुनवाई की गई।

अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अजमेर दरगाह शरीफ के पूरे क्षेत्र में स्थानीय निकाय की स्वीकृति के बिना कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जा सकती। इसके साथ ही अदालत ने यह भी आदेश दिये कि निकाय इस जगह का फिर से सर्वे करे और अवैध रूप से बनाई जा रही दुकानों पर कानून के अनुसार कार्रवाई करे।

इस मामले में सैयद काजमी चिश्ती द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी और याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी के

■ जहाँ अनाधिकृत दुकानों का निर्माण हुआ है, वहां निगम ने केवल जनसुविधाओं के लिए नक्शा पास किया था।

■ पुरानी जनसुविधाएँ सन् 1917 में निर्मित हुई थीं, जिन्हें तोड़ दिया गया था और फिर 2017 में निगम ने नई जन सुविधाएँ बनाने का नक्शा पास किया था।

■ परंतु दरगाह दीवान ने एक प्राइवेट पार्टी से उक्त स्थान पर व्यावसायिक दुकानें बनाने का अनुबंधन कर लिया।

लिये अधिवक्ता आशीष सक्सेना पेश हुए थे।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आशीष सक्सेना ने अदालत को बताया कि दरगाह परिसर में 1917 में फैसिलिटी प्रिया बनाया गया था परंतु कई वर्षों से जर्जर हालत में होने के कारण निकाय ने पहले तो इस फैसिलिटी प्रिया में निर्मित शौचालयों के उपयोग पर रोक लगाई फिर वर्ष 2017 में 30 से 40 नये शौचालयों और एक वेटिंग रूम का

निर्माण करने की योजना पारित की।

बहस के दौरान आशीष सक्सेना ने बताया कि प्रात दस्तावेजों से साबित होता है कि दरगाह दीवान ने एक प्राइवेट पार्टी के साथ एम.ओ.यू. किया था, जिसके तहत फैसिलिटी प्रिया के ग्राउंड फ्लोर पर कुछ दुकानों का भी निर्माण किया गया है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि 27 मार्च 2017 में निगम ने जिस फैसिलिटी प्रिया के प्लान को स्वीकृति दी थी, उनमें दुकानों का विवरण

ताईवान के लिए अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया में छः परमाणु बॉम्बर्स तैनात किये

सिडनी, 1 नवम्बर। अमेरिका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में एक एयरबेस पर छह परमाणु-सक्षम बी-52 बॉम्बर्स भेजने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी दस्तावेजों का हवाला देते हुए, स्थानीय ब्राडकास्टर एबीसी ने बताया कि वाशिंगटन ने ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में डार्विन शहर से लगभग 300 किमी दक्षिण में टिंडल एयर बेस पर विमान के लिए समर्पित सुविधाओं के निर्माण के लिए विस्तृत योजना तैयार की थी।

ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विभाग ने रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अमेरिकी वायु सेना ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में बॉम्बर्स तैनात करना हमारे विरोधियों को एक मजबूत संदेश भेजता है। अमेरिका के इस कदम से चीन भड़क गया है।

एक्सपर्ट्स ने बताया कि यह कदम चीन के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि चीन ताइवान पर आक्रमण कर सकता है। ऐसे में यदि ताइवान में चीन कोई भी चलाकी करने की कोशिश करता है तो फिर अमेरिका इन बॉम्बर्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन

■ एटॉमिक बॉम्बर्स तैनात करके अमेरिका ने चीन को बहुत ही कड़ा संदेश दे दिया है कि, अगर ताईवान में चीन कोई भी चलाकी करता है तो, अमेरिका तुरंत ही अपनी युद्धक प्रतिक्रिया देगा।

■ अमेरिका के इस कदम से चीन आगबबूला हो गया है और आरोप लगाया है कि, अमेरिका के इस कदम से हमारे क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा होगी।

सिक्वोरिटी के बेक्का वासेर ने कहा, “चीन की मुख्य भूमि पर संपातित रूप से हमला करने वाले बॉम्बर्स विमान चीन को एक संकेत भेजने में बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं यदि चीन ताइवान पर कुछ आगे कार्रवाई करता है तो। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के साथ तनाव ने उत्तरी ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण डिफेंस सेंटर बना दिया है और इस क्षेत्र में अपनी सैन्य संपत्ति को अपग्रेड करने के लिए 1 अरब डॉलर खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विमान निर्माता के अनुसार, बोइंग द्वारा डिजाइन और निर्मित बी-52 अमेरिकी की लिस्ट में सबसे अधिक

लड़ाकू-सक्षम बॉम्बर्स हैं। लंबी दूरी के भारी बॉम्बर्स अमेरिकी वायु सेना की रीढ़ रहे हैं और परमाणु व पारंपरिक दोनों हथियारों को तैनात करने में सक्षम हैं। एबीसी ने अमेरिकी वायुसेना के हवाले से कहा कि बॉम्बर्स की मेजबानी करने और संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास करने की ऑस्ट्रेलिया की क्षमता दिखाती है कि हमारी दो वायुसेनाएं कितनी एकीकृत हैं।

वहीं, इससे संबंधित पूछे गए एक सवाल में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लियिनयन ने कहा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी तीसरे पक्ष को निशाना बनाने के लिए नहीं है।

रेलवे को इस साल बम्पर कमाई हुई

■ रेलवे की आय में 17 प्र.श. की बढ़ोतरी हुई।

करोड़ टन था। वहीं मासिक आधार पर अक्टूबर में रेलवे ने 11.89 करोड़ टन माल की ढुलाई की जो अक्टूबर, 2021 में 11.73 करोड़ टन थी। इस तरह अक्टूबर के महीने में माल ढुलाई में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

पिछले महीने में रेलवे ने माल ढुलाई से 13,353 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया जो एक साल पहले के 12,313 करोड़ रुपये की तुलना में आठ प्रतिशत अधिक है। रेलवे ने इसका श्रेय हंग्री फॉर कार्गो योजना के देते हुए कहा कि प्रतिस्पर्धी दरों पर मालवहन सुविधा देने के लिए कई बदलाव किए गए हैं।

वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में रेलवे ने कुल 85.56 करोड़ टन वजन की ढुलाई की जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 78.62

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रभावहीन हो गए। आंध्र प्रदेश में उनके छोटे भाई संदीपन जो फिल्म स्टार भी हैं, ने भी “जन सेना” नामक अपनी पार्टी बनाई।

यह पार्टी कभी भाजपा के साथ मेल-जोल रखती दिखाई देती है तो कभी-कभार तेलुगुदेशम के साथ। यही कारण है कि आंध्र प्रदेश में चिरंजीवी की राजनैतिक योजनाओं की चर्चा करना दिलचस्पी भरा है, क्योंकि आंध्र में इस समय वाई.एस.आर. के पुत्र जगन मोहन रेड्डी का शासन है। जिनकी राज्य पर जबरदस्त पकड़ है तथा राज्य की राजनीति में उनका दबदबा है। आंध्र के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ ही होंगे तथा यहाँ से 25 सांसदों की अच्छी-खासी संख्या लोकसभा में जाती है। जहाँ तक संसद का संबंध है, वाई.एस.आर. वहाँ

हिन्दुस्तान ने रूस के फैसले पर गम्भीर चिंता जताई

रूस ने घोषणा की है कि, वह संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में यूक्रेन के साथ हुये अनाज निर्यात समझौते के क्रियान्वयन को तत्काल निलंबित करेगा

नई दिल्ली, 1 नवम्बर। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे दुनिया के कई देशों पर रूस के एक फैसले से भुखमरी का खतरा और बढ़ गया है। रूस ने शनिवार को कहा था कि वह संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हुए अनाज निर्यात समझौते के क्रियान्वयन को तत्काल निलंबित करेगा। इस समझौते की वजह से यूक्रेन से नौ करोड़ टन से अधिक अनाज का निर्यात हुआ था और वैश्विक स्तर पर खाद्य कीमतों में कमी आई थी। लेकिन अब रूस के फैसले से चिंताएं एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं। भारत जैसे मित्र देश ने भी रूस के इस कदम पर चिंता व्यक्त की है।

भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र को मध्यस्थता से हुए काला सागर अनाज समझौते को निलंबित किए जाने से दुनिया के सामने मौजूद खाद्य सुरक्षा, ईंधन और उर्वरक की आपूर्ति संबंधी चुनौतियां और

■ हिन्दुस्तान ने कहा कि, रूस के एक फैसले के कारण पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे दुनिया के कई देशों के लिए भुखमरी का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है।

बढ़ने की आशंका है। इस समझौते के तहत रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन से खाद्य सामग्री का निर्यात किया जा रहा था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में कार्डेसलर आर. मधुसूदन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रयासों के परिणामस्वरूप हुए अनाज समझौते का उद्देश्य वैश्विक खाद्य संकट को टालना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

काला सागर अनाज समझौते पर सोमवार को सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग के दौरान मधुसूदन ने कहा, “काला सागर अनाज समझौते और पक्षों के बीच

सहयोग ने अब तक यूक्रेन में शांति के लिए आशा की एक किरण पैदा की थी...हमारा मानना है कि काला सागर अनाज समझौते के निलंबन से दुनिया और विशेष रूप से दक्षिणी हिस्से के सामने खाद्य सुरक्षा, ईंधन और उर्वरक आपूर्ति चुनौतियां और बढ़ने की आशंका है।” उन्होंने कहा कि भारत “यूक्रेन व रूस से खाद्य एवं उर्वरक के निर्यात की सुविधा शुरू करने और समझौते को नया रूप देकर उसके पूर्ण कार्यान्वयन” की संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरिस की अपील का समर्थन करता है।

रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप में स्थित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने चेतावनी दी कि यूक्रेन के अनाज का निर्यात करने के समझौते को रूस द्वारा निलंबित करने से वैश्विक भुखमरी बढ़ेगी। डेलवेयर के बिलिंगमटन में बाइडन ने कहा, “यह वाकई अपमानजनक है। वे क्या कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है।” रूस ने घोषणा की थी कि वह समझौते के क्रियान्वयन को तत्काल रोक देगा। उसने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने शनिवार को रूस के काला सागर बेड़े के जहाजों पर झोन से हमला किया था।

यूक्रेन ने रूस को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया

लंदन, 1 नवम्बर (वार्ता)। यूक्रेन में पिछले 24 घंटे के दौरान रूस के एक हजार से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, जो रूस के लिए अब तक का सबसे बड़ा नुकसान और झटका है। समाचार पत्र ‘द सन’ ने मंगलवार को अंतिम रिपोर्ट में यह जानकारी दी। यूक्रेन ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में रूस के करीब एक हजार सैनिक मारे

■ यूक्रेन ने 24 घंटों में रूस के एक हजार से ज्यादा सैनिक मार दिये हैं।

गए हैं जो कि रूस के लिए अब तक का सबसे जबरदस्त झटका है।

समाचार पत्र के अनुसार युद्धग्रस्त देश रूस लगातार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना को पीछे धकेल रहा है और ताजा रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की सेना ने रूस के सैकड़ों सैनिकों का सफाया किया है। यूक्रेन का दावा है कि रविवार को उसने रूस के 950 को मार गिराया है।

गौरतलब है कि आठ महीने पहले शुरू हुए हमलों में यह एक दिन में सबसे ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की घटना है।

इसके साथ ही अभी तक मारे गए रूसी सैनिकों की कुल संख्या 71,200 तक पहुँच गयी है।

ई.वी.एम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

‘एटॉम’ जनरल आर. वेंकटरमानी ने भी याचिका का विरोध तथा कहा कि व्यक्ति अपनी पसंद ई.वी.एम. तक पहुँचने से पहले ही तय कर लेता है। “चुनाव चिन्ह की जगह फोटो लुगाने की मांग करने वाली याचिका से मैं सहमत नहीं हूँ। चुनाव चिन्ह राजनैतिक दलों की पहचान होते हैं।”

दिल्ली के वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका दायर की और ई.वी.एम. पर पार्टी के निशान के इस्तेमाल को अवैध, असंवैधानिक तथा संविधान के अनुच्छेद 14,15 व 21 का उल्लंघन करार देने की घोषणा करने के लिए निर्देश मांगा। याचिका का कहना है भ्रष्टाचार व राजनीति के अपराधिकरण को हटाने का एक ही तरीका है कि मत पत्र और ई.वी.एम. से पार्टी का निशान हटाकर प्रत्याशी का नाम उम्र व शैक्षणिक योग्यता लिखी जाए। याचिका कहती है कि पार्टी चिन्ह के बिना मतपत्र व ई.वी.एम. होने से मतदाताओं को ईमानदार व योग्य न्यायाधियों को चुनने में मदद मिलेगी।

वॉट्सऐप ने दो महीने में भारत में 49 लाख अकाउन्ट बैन किये

नई दिल्ली, 1 नवम्बर। वॉट्सऐप के स्वामित्व वाली कंपनी मेटा ने भारत में 26 लाख से अधिक आपत्तिजनक अकाउन्ट्स को बैन कर दिया है। मंगलवार को इसके बारे में जानकारी देते हुए कंपनी ने आई.टी. नियम 2021 का हवाला दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत कंटेंट अपलोड एवं प्रसारित किये थे, कंपनी ने सितम्बर के महीने में इन लोगों की मॉनिटरिंग की थी और जांच में पाया गया कि, ये अकाउन्ट बैन किये जाने योग्य हैं।

गौरतलब है कि, वॉट्सऐप भारत में एक सबसे अधिक लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में से एक है, जिसके देशभर में लगभग 50 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं, भारत में सितंबर में 666 शिकायत रिपोर्ट प्राप्त हुईं और 23 शिकायतों पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी। कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “आई.टी. नियम 2021 के अनुसार, हमने सितंबर 2022 के महीने की रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस यूजर-सेफ्टी रिपोर्ट में प्राप्त शिकायतों और

■ वॉट्सऐप ने इसके पीछे नये आई.टी. रूस का हवाला दिया है तथा कहा है कि, जांच में ये अकाउन्ट्स आपत्तिजनक कन्टेंट का प्रसार करते हुये पाये गये हैं।

■ गौरतलब है कि, वॉट्सऐप भारत में एक सबसे अधिक लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में से एक है, जिसके देशभर में लगभग 50 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं।

व्हाट्सऐप द्वारा की गई संबंधित कार्रवाई का विवरण है, साथ ही, इसमें हमारे प्लेटफॉर्म पर दुरुयोग से निपटने के लिए व्हाट्सऐप द्वारा की गई कार्रवाई भी शामिल हैं।”

प्लेटफॉर्म ने अगस्त में भारत में 23 लाख से अधिक अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया था। नए आई.टी. नियम 2021 के तहत प्रमुख डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें पांच मिलियन से अधिक यूजर्स हैं, उन्हें मार्सिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है।

इस बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और आई.टी. मंत्रालय ने डिजिटल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ

संशोधनों को अधिसूचित किया है। वर्तमान में सोशल मीडिया मध्यस्थों को केवल यूजर्स को गलत कंटेंट की कुछ कैटेगिरीज को अपलोड नहीं करने के बारे में सूचित करने की आवश्यकता होती है। यूजर्स को ऐसे कंटेंट अपलोड करने से रोकने के लिए उचित प्रयास करना मध्यस्थों का एक कानूनी दायित्व है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि, भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है।

मंत्रालय द्वारा सभी स्ट्रेकहॉल्डर्स को शामिल करने हुए एक विस्तृत सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया का पालन करने के बाद संशोधनों को अधिसूचित किया गया था।

वायर च्यूज...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

डालकर उनके डिजिटल उपकरण जब्त कर लिए गए। संयुक्त बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने भाजपा के नेशनल आई.टी. विभाग के मुखिया को शिकायत पर अंतक मचाया था और इसमें प्रक्रिया का जरा भी ध्यान नहीं रखा गया। एफ.आई.आर. में वायर के संचालकों पर मानहानि, धोखाधड़ी, ठगी और अपराधिक षडयंत्र के आरोप लगाए गए हैं। ये सब आरोप एक न्यूज पोस्ट की वजह से लगाए गए हैं जबकि पोस्टल ने वह न्यूज हटा दी थी। वायर द्वारा जारी बयान के अनुसार ब्राह्म ब्रांच उनके ऑफिस हाईडिस्क, फोन, आई पेंड्र और कम्प्यूटर ले गए।